

# विकास भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 304 | गुवाहाटी | शनिवार, 7 जून, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHN/2014/56526

भगदड़ : विराट कोहली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज

पेज 2

मुख्यमंत्री ने दूसरी बार बराक घाटी का किया निरीक्षण, हैलाकांदी व श्रीभूमि...

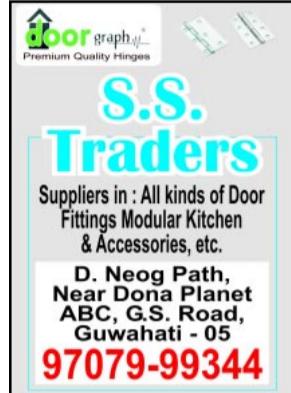
पेज 3

राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी को देश से मांगनी चाहिए माफी : नायब सैनी

पेज 5

शुभमन गिल के टेस्ट कपानी की शुरुआत : स्पष्टता...

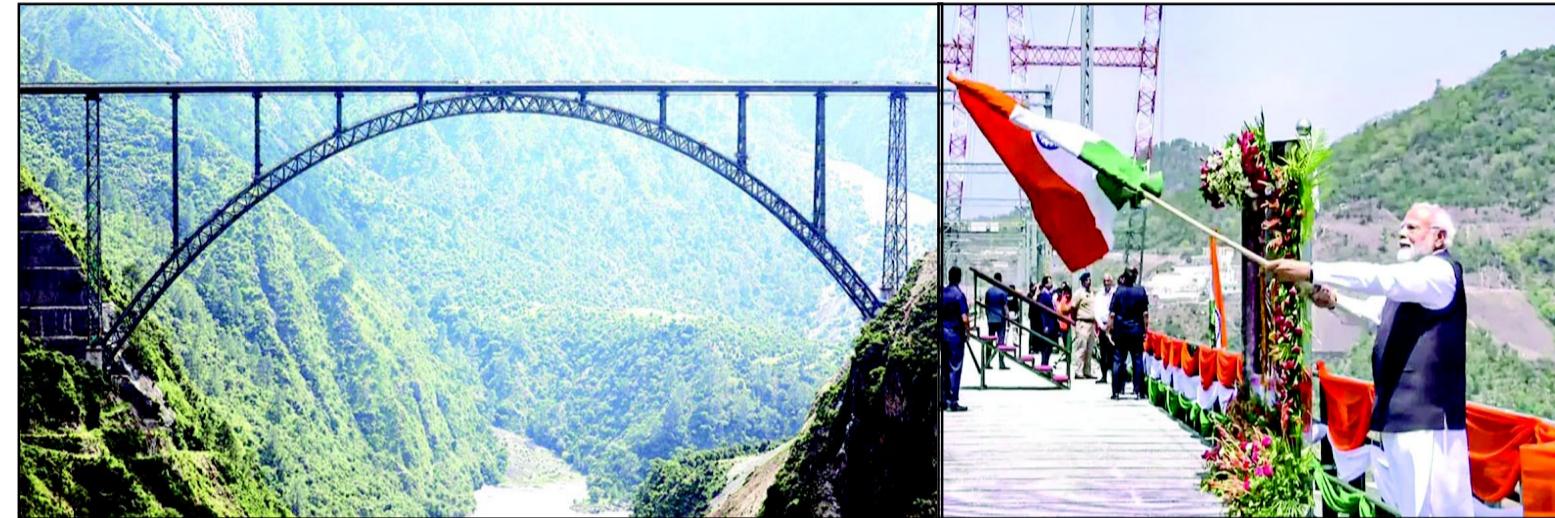
पेज 7



## न्यूज गैलरी

बाढ़ की स्थिति में सुधार, अभी भी 41 हजार राहत शिविरों में गुवाहाटी। असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार के संकेत मिले हैं, हालांकि राज्य के 16 जिलों में 5.60 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। असम राज्य अपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एप्सीडीएमए) के अनुसार, 1,400 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के पानी ने 1,900 हेक्टेयर से -शेष पृष्ठ दो पर

## पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन



### वंदे भारत की भी दी सौगात

नई दिल्ली/जम्बू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्बू-कश्मीर के दोरे पर पहुंचे और राज्य के 46 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित कीं। इस दौरान उन्होंने दो ऐतिहासिक और तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय पुलों चिनाब ब्रिज और अंजी पुल का उद्घाटन किया। साथ ही कट्टा से श्रीनगर के बीच चलने वाली बड़े भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रखना किया। चिनाब नदी पर बना चिनाब ब्रिज अब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आचं ब्रिज बन चुका है। इसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी अधिक है और वह समुद्र तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह पुल उनके केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से वेमिसाल है, बल्कि यह देश के हर कोने को कश्मीर घाटी से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह पुल उत्तमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो जम्बू-कश्मीर के भौगोलिक और भावनात्मक दोनों रूपों में भारत से जोड़ने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री -शेष पृष्ठ दो पर

वाली बड़े भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रखना किया। चिनाब नदी पर बना चिनाब ब्रिज अब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आचं ब्रिज बन चुका है। इसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी अधिक है और वह समुद्र तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह पुल उनके केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से वेमिसाल है, बल्कि यह देश के हर कोने को कश्मीर घाटी से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह पुल उत्तमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो जम्बू-कश्मीर के भौगोलिक और भावनात्मक दोनों रूपों में भारत से जोड़ने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री -शेष पृष्ठ दो पर

### पहलगाम हमले ने इंसानियत और कश्मीरियत पर किया प्रहार, लेकिन विकास नहीं डिगेगा : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (हिस्स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जम्बू-कश्मीर के दोरे पर पहुंचे और राज्य के 46 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित कीं। इस दौरान उन्होंने दो ऐतिहासिक और तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय पुलों चिनाब ब्रिज और अंजी पुल का उद्घाटन किया। साथ ही कट्टा से श्रीनगर के बीच चलने वाली बड़े भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रखना किया। चिनाब नदी पर बना चिनाब ब्रिज अब विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आचं ब्रिज बन चुका है। इसकी ऊंचाई एफिल टॉवर से भी अधिक है और वह समुद्र तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह पुल उनके केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से वेमिसाल है, बल्कि यह देश के हर कोने को कश्मीर घाटी से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह पुल उत्तमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो जम्बू-कश्मीर के भौगोलिक और भावनात्मक दोनों रूपों में भारत से जोड़ने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री -शेष पृष्ठ दो पर

### जी-7 सम्मेलन में हिस्सा लेने कनाडा जाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और उन्हें जी-7 सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने आमंत्रण के लिए उन्हें ध्यानावाद दिया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में उनसे मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। इस साल 15 से



17 जून 2025 को अल्बर्टा के कनानारिक्स में जी-7 सम्मेलन हो रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारत ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और -शेष पृष्ठ दो पर

### खराब जल निकासी से जुड़ी कृत्रिम बाढ़ पर सीएम ने जताई चिंता

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने डिक्कू गाढ़ और सिलचर ज़ेसे शहरों में कृत्रिम बाढ़ में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में अपर्याप्त जल निकासी और अनियोजित शहरी विकास को चिह्नित किया है। शर्मा ने कहा कि खाली पड़ी जमीन पर निर्माण कार्य प्राकृतिक जल प्रवाह को बाहित करता है, जिससे शहरी क्षेत्रों में जलभाव की समस्या और -शेष पृष्ठ दो पर



## Ceremonial Distribution

of Joint Transfer Order

### Swagata Satirtha Portal

for mutual transfer of Grade III and Grade IV employees

#### Chief Guest

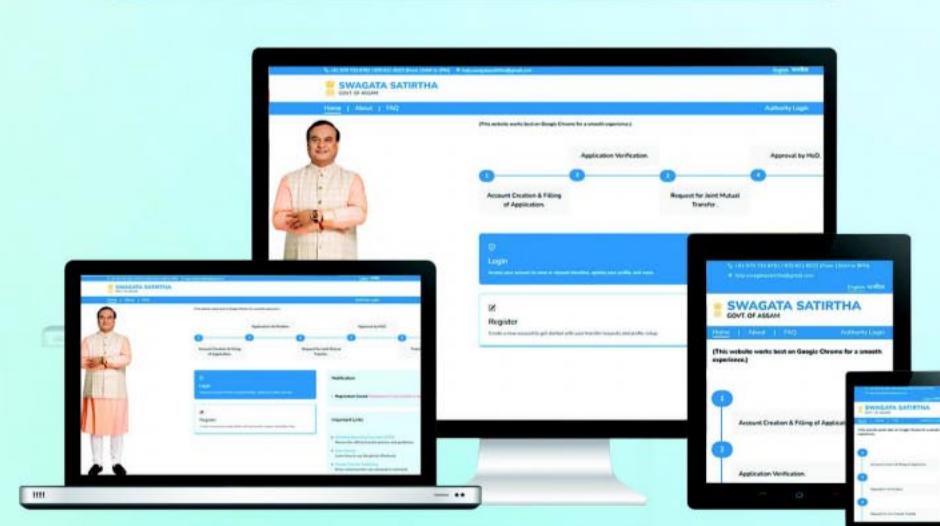
**Dr. Himanta Biswa Sarma**  
Chief Minister, Assam

Total Mutual Transfer Applications Approved

**4502**

No. of Employees Benefitted

**9004**



■ 7 June 2025 | 4:00 PM

Ground Floor, Lok Sewa Bhawan, Dispur





संपादकीय

## न्याय की साख

**बढ़ते** तापमान, बदलते जलवायु एवं ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से रहे हैं। जिससे समुद्र किनारे बसे अनेक नगरों एवं महानगरों के ढूबने का खतरा मंडराने लगा है। इसानों को प्रकृति, पृथ्वी एवं पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिये वैश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो पर्यावरण, प्रकृति एवं पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोज्य यह दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन के साथ एक जटिल समस्या है, इसीलिये 2025 में इस दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। कोरिया गणराज्य वैश्विक समारोह की मेजबानी करेगा। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, यह हमारे पानी के पानी, हमारे खाने, हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण में समा रहा है। इस प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प निश्चित ही एक समाधान की दिशा बनेगा। हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई केवल एक बारात उपयोग के लिए होता है और जल्दी ही फेंक दिया जाता है। 1973 से संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोज्य यह दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन के साथ एक जुट करता है। बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की एक गंभीर एवं जटिल समस्या है, इसीलिये 2025 में इस दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। कोरिया गणराज्य वैश्विक समारोह की मेजबानी करेगा। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, यह हमारे पिने के पानी, हमारे खाने, हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण में समा रहा है। इस प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प निश्चित ही एक समाधान की दिशा बनेगा। हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई केवल एक बार उपयोग के लिए होता है और जल्दी ही फेंक दिया जाता है।

पारास्थितका तत्र का भूत क्षमा म बदल  
रहा है और मानव जीवन पर तरह-तरह के खतरे पैदा कर रहा है। प्रकृति को पस्त करने, वायु एवं जल प्रदूषण, कृषि फसलों पर धातक प्रभाव, मानव जीवन एवं जीव-जन्तुओं के लिये जानलेवा सावित होने के कारण समूची दुनिया में बढ़ते प्लास्टिक एवं माइक्रोप्लास्टिक के कण एक बड़ी चुनौती एवं संकट है। पिछले दिनों एक अध्ययन में मनुष्य के मस्तिष्क में प्लास्टिक के नैनो कणों के पहुंचने पर चिंता जातायी गई थी। दावा था कि प्रतिदिन सैकड़ों माइक्रोप्लास्टिक कण सांसों के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे तमाम नये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध-सर्वेक्षण-अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सांसों, प्रकृति, पर्यावरण, पेयजल, व फसलों में धातक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी एक गंभीर संकट है। संकट तो यहां तक बढ़ गया है कि प्लास्टिक के कण पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में शामिल कई खाद्यान्नों की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। ऐसा निष्कर्ष अमेरिका-जर्मनी समेत कई देशों के साझे अध्ययन के बाद सामने आया है। दरअसल, प्लास्टिक कणों के हस्तक्षेप के चलते पौधों के भोजन सृजन की प्रक्रिया बाधित हो रही है।

## आप का नजरीया

## पर्ची फीस की गारंटी

**हिमकेयर** से गुजरते हिमाचल ने जो साधुवाद दिया है, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए सरकार की बजटीय कोशिकाओं में नई ऊर्जा चाहिए। बहरहाल तीन बड़े अस्पतालों के लंबित हिम केयर भुगतान की राशि से 43.19 करोड़ जारी हो गए। यानी जिन पर्चियों पर हिमकेयर का मजमून लिखा था, उन्हें इस भुगतान से कुछ आराम मिलेगा। हिमकेयर एक अच्छी योजना की अच्छी कहानी बन सकती थी, वशर्ते कार्यान्वयन की पद्धति में ईमानदार निगाह होती। किसी भी सरकारी धन का व्यय बजट की इज्जत के दायरे में होना चाहिए, लेकिन 'हिमकेयर' के इस्तेमाल में न परिभाषा और न ही इसकी उपयोगिता का उचित प्रबंधन रहा, नतीजतन एक पहाड़ सा भुगतान चिकित्सा के बाजुओं को उठाना पड़ रहा है। बहरहाल, हिमकेयर के भुगतान का छोटा सा उपहार भी टीएमसी और आईजीएमसी के वित्तीय दस्तावेजों को सहारा देगा, लेकिन अब चुनौती पूरे चिकित्सा तंत्र को आत्मनिर्भर बनाने तथा इसकी योग्यता को चमकाने की सामग्रे आ रही है। ऐसे में सरकारी अस्पताल की पर्ची बनाने का शुल्क अगर दस रुपए निर्धारित हो रहा है, तो यह एक सही कदम है। अब इसके ऊपर बहस हो सकती है कि पर्ची फीस दस हो या बीस से पचास रुपए करनी चाहिए। लोग इलाज को अब गुणवत्ता के लिहाज से देख रहे हैं। अगर दस रुपए की पर्ची पर भी मरीज अगले अस्पताल ही रैफर होने हैं, तो क्या चूं चूं और क्या चूं चूं का मरब्बा। आशर्च्य होता है जब क्षेत्रीय या जोनल अस्पताल अपने मरीजों का मामूली इलाज करने के बजाय इन्हें आसपास के मेडिकल कालेजों की ओर रवाना कर देते हैं। ऐसे में अस्पतालों की रैकिंग के मुताबिक चिकित्सा सेवाओं का गारंटी पत्र टंगा होना चाहिए। एक डिस्पेंसरी की पर्ची दस रुपए हो

सत्ताजा का नाम पर उन हालों पाहटा, इन डिपेसर का नाम दस रुपए है, सिविल अस्पताल की बीस, क्षेत्रीय की तीस रुपए, जोनल की पचास, तो मेडिकल कालेज की सौ रुपए कर दी जाए, लेकिन पर्ची फीस की गारंटी भी हो जाएगी। बीमारी की पहचान व उसके निदान के लिए हर स्तर के अस्पताल के मानदंडों के अनुसार निश्चित होने चाहिए। अगर प्रसव पीड़ा के समय जोनल अस्पताल धर्मशाला के बड़े खाली रहते हुए, मरीज को टांडा भिजवा दें, तो यह पर्ची नहीं, एक धोखा होगी। अगर जिला स्तरीय अस्पतालों में मरीजों को पूर्ण चिकित्सा के प्रमाणानुसार प्रति के रूप में पर्ची के लिए दस से पचास रुपए भी अदा करने पड़ते हैं, तो वह हिमाचल की जनता सरकारी संस्थानों पर अपना विश्वास पेश करेगी, वरना उसकी मेडिकल कालेज भी किस काम के। हर दिन हिमाचल मेडिकल कालेजों की विज्ञापनों में आज तक यह बात नहीं आयी है। अब यह एक बड़ी बात हो गई। पर्ची पर अगर रैफरल टिप्पणियां ही जान बचाएंगी, तो क्या फर्क पड़ता है। अलग सरकार के समर्थन में पर्ची फीस, टेस्टों के बड़े हुए दाम तथा अन्य सुविधाओं के लिए शुल्क अदा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते चिकित्सा सुविधाएं जीवन सुरक्षा की गारंटी बनें। आज हिमाचल के निजी क्षेत्र के तहत दर्जनों ऐसे अस्पताल कार्यरत हैं, जहां अधिक खर्च करके भी जनता सिर्फ इसके विश्वास के साथ आ रही है कि कम से कम वहां जीवन बचाने का हर संभव प्रयास होगा। दूसरी ओर जीवन बचाने के लिए जब सरकारी संस्थानों में हाथ उठाया जाए जाते हैं, तो सलाह मिलती है किसी बाहरी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए जाने की। ऐसे में हिमाचल को अपने अस्पतालों को अलग-अलग कीटेगरी में डाल कर पर्ची फीस व अन्य शुल्क निर्धारित करने होंगे। प्रयोग के तौर पर किसी बड़ी चिकित्सकीय श्रृंखला के साथ अनुबंध करके अपने कुछ प्रमुख अस्पतालों में अलग से सपरस्पैशियलिटी विंग खोल देने चाहिए।

प्रमोद भार्गव

6

चीन के पिंडू पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के सलाहकार राणा अहसान अफजल ने एक नई धमकी देते हुए कहा है कि यदि चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे तो भारत का क्या हाल होगा ? चूंकि पाकिस्तान न तो ब्रह्मपुत्र के भूगोल से पराजित है और न ही पानी के प्रवाह के तकनीकी के ज्ञान से ? इसलिए इस भूगोल और तकनीक का ज्ञान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कराकर पाक के नैरेटिव की हवा निकाल दी । बिस्वा ने अपनी एक्स पोस्ट पर ठोस तथ्यों के साथ लिखा कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है, जिसका प्रवाह भारत में घटता-बढ़ता नहीं है । अतएव नदी को अपना प्रवाह बनाए रखने के लिए चीन के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है । ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में चीन केवल 30 से 35 प्रतिशत तक का योगदान देता है । यह भी ज्यादातर हिमनदों के पिघलने और बारिश से मिलता है । शेष 65 से 70 प्रतिशत जल भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलता है । इसलिए यह नदी भारत में प्रवेश के बाद सश्वत हो जाती है ।

देश दुनीया से

दुनीया से

# कैंसर पर जीत के बाद विश्व सुंदरी का खिताब

ਪਿੰਡਲ

पिछले दिना भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता की दावेदारी भले ही विश्व बीस तक सिमट कर रह गई हो, लेकिन थाईलैंड की सुंदरी ओपल सुचाता ने विश्व सुंदरी का खिताब हासिल करने के बाद कहा कि उनका ताज सिर्फ थाईलैंड का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि वह उन करोड़ों महिलाओं की आवाज भी है, जिन्हें अनसुना किया गया। वे उनके हक के लिये खड़ी होंगी। दरअसल, ओपल ने अटारह वर्ष की उम्र से सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। उनका मानना था कि उनका सौंदर्य स्पर्धाओं में भाग लेना नेम-फैम कमाना ही नहीं था, बल्कि इस उपलब्धि को उद्देश्यपूर्ण बनाना ही मुख्य लक्ष्य था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर थाईलैंड की संस्कृति को भी सम्मान दिलाना एक मकसद था। उल्लेखनीय है कि ओपल वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स स्पर्धा में थाईलैंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तब वह तीसरे स्थान पर आई थीं। मिस वर्ल्ड स्पर्धा के लिये उन्होंने वह खिताब छोड़ दिया। उनका मानना है कि इस खिताब को हासिल करने का उनका मुख्य मकसद यह है कि वे सामाजिक बदलाव को बाहक बन सकें। ओपल का मानना है कि यह खिताब सिर्फ सौंदर्य मानकों पर खरा उतरना मात्र नहीं है। ओपल मानती है कि यह लोगों के लिये सुंदर काम करने के लिये दिया गया खिताब है। वे उस भारतीय दर्शन की हाथी हैं कि दैहिक सौंदर्य अल्पकालिक होता है, लेकिन सुंदर उद्देश्य सार्वकालिक होता है। उनका एक सपना यह भी है कि वे एक दिन राजदूत बनें। दरअसल, 21 वर्षीय ओपल वर्षों से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी महिलाओं के लिये काम कर रही हैं। वैसे तो हर विश्व सुंदरी अपनी जीत के बाद समाज सेवा आर करुणा के प्रति प्रातबद्धता जतान म पाठ्य नहीं रहती, लेकिन कैंसर ओपल का भोग यथार्थ है। वे उस त्रासदी से गुजरी हैं और कैंसर पीड़ितों के दर्द को करीब से महसुस करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता का प्रसार करने वाले कई सामाजिक संगठनों के साथ सक्रिय भागेदारी की है। उनका मानना है कि वे नई जिम्मेदारियों के बावजूद ब्रेस्ट कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती रहेंगी। उनका कहना है कि महिलाओं को रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए। उन्हें डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि इस महामारी का समय रहते पता चल जाए तो इससे बचाव संभव हो सकता है। उनका कहना है कि मैं इस मुद्रे पर लगातार महिलाओं से बात करती रहना चाहूँगी। ओपल बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान व मानव से जुड़े विज्ञान में उनकी गहरी रुचि भी है। इतना ही नहीं वे जीव-जंतुओं के प्रति गहरी संवेदना रखती हैं। उनका पशु प्रेम इस बात से झलकता है कि उनके घर में दर्जन से अधिक बिल्लियां व करीब आधा दर्जन कुते पलते हैं। बहरहाल, विश्व सुंदरी के खिताब से मिली प्रतिष्ठा के साथ ओपल आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर व समृद्ध हुई है। उनकी तमाम योजनाएं अब सिरे चढ़ने वाली हैं क्योंकि इस खिताब के साथ-साथ उनके खाते में एक मिलियन डॉलर भी आए हैं। वहीं दूसरी ओपल भारतीय संस्कृति व फिल्मों के प्रति भी खासा लगाव रखती है। पिछले दिनों खिताब जीतने के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्में उन्हें आकर्षित करती हैं।

ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ

## कोण

## सुरक्षित

**सुरक्षित** पर्यावरण ही सुरक्षित मनुष्य जीवन का आधार है। हमारी धरती, जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। विश्व के देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राह में दिनोंदिन दुनिया भर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ गया है और इस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, जिससे पर्यावरण खतरे में है। इनसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। ऐसे में प्रकृति के साथ इनसानों को तालमेल बिठाना होता है। लेकिन लगातार वातावरण दूषित हो रहा है जिससे कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, जौ हमारे जनजीवन को तो प्रभावित कर ही रही हैं, साथ ही कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की भी वजह बन रही हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो भारत को वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भारत को 180 देशों में से सबसे कम रैंक वाले पांच देशों में से एक बनाता है, जोकि चिंता जनक है। वायु और जल प्रदूषण की दृष्टि से भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदृष्टि शहरों

जीवन का जनजीवन कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा उत्सर्जक है, हालांकि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में कम पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अधिनियम द्वारा इस को सांकेतिक किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को कानून के रूप में लागू करता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ओर, पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ रहा है। भारत को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरण समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने वाला आवश्यकता है क्योंकि सुखी स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

## आधुनिकता की ढौड़ में पर्यावरण के उभरते खतरे

नागरिकों का दायित्व बनता है कि इस आधुनिकता की दौड़ को छोड़कर अपने गांव में शिक्षा संस्थानों में या कार्यालयों में पौधा अवश्य लगाएं ताकि वह पर्यावरण को स्वच्छ और साफ-सुथरा रखने के लिए अनिवार्य हो और आपका यादगार भी बनी रहे। दुनिया में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ रहा है जिसे रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस मनाने की शुरूआत हुई, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। भारत भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। इसी कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने कानून बनाया है। 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था तो भारत में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में प्रकृति के प्रति अपनी चिंताओं को जाहिर किया था। पर्यावरण समाज का एक हिस्सा है।

अलग

अलगा

नहीं जाने को टीस...

प्रदे

**प्रदेश** साहित्य अकादमी का इस्यंग विधा का आयोजन करवा रही थी। मुझे भी बुलाया था, मैंने अतुल जी से कह दिया- 'यह गंभीर विषय है। किसी स्कॉलर को बुलाओ, वही रंग जमा सकता है। मैं व्यंग्य के गंभीर आलोचना पक्ष से अनभिज्ञ हूँ'। अतुल जी को बात लग गई। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन उनको मेरा अपहयोग अच्छा नहीं लगा। आयोजन अखिल भारतीय स्तर का था, अतः अतुल जी उन लागों को बुलाना नहीं भूल थे, जो उनके व्यंग्य कर्म को पहचान दे सकें। उनमें दो-तीन समाचार-पत्रों के संपादक भी थे, वे भी अतुल जी को अपने पत्रों में स्थान दे रहे थे। मुझे इसकी आवश्यकता थी भी नहीं, मैंने अपनी व्यंग्य यात्रा बिना बैसाखियों के ही प्रारंभ की थी और वह अभी तक जारी है। चूंकि अतुल जी आयोजन सचिव थे, उन्हें अकादमी से अपनी पुस्तक को भी पुरस्कृत करवा कर प्रकाश में लाना था, अतः वे परे मनोयोग से लगे हुए थे। मेरा व्यंग्य मार्केट पहले ही अखिल भारतीय पहचान ले चुका था और यही बात मेरी मनाही से आयोजकों को खटक रही थी। पत्रवाचन में बरबार खतरा यह बना हुआ था कि कहीं मेरे नाम का आयोजन सभा में नामोल्लेख न हो जाए। अतुल जी ने एक दिन पूर्व ही कि मैं इतना लिख-पढ़ रहा हूँ कि पत्रवाचक मेरा नामोल्लेख करना भूलेंगे नहीं। एक संभागी ने सुझाव दिया कि हमें पत्रवाचकों को पहले ही ताकीद देनी होगी कि वे शर्म का नामोल्लेख करने से जितना संभव हो उतना तो बचें ही बचें। दूसरे संभागी ने कहा कि जब हम पत्रवाचकों को पेमेंट कर रहे हैं तो ताकीद क्या करना, एकदम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वे शर्म का व्यंग्य योगदान नकार दें। तीसरा बोला- 'यारो यह शर्मा न सभा-संगोष्ठियों में जाता है न हमारे साथ उठता-बैठता है, फिर क्यों कर इसका मूल्यांकन हो। समझ में नहीं आता कि इसे व्यंग्य से आउट कैसे किया जाए?' यह तौ मेरी भी यही है कि बिना इसे सबक सिखाए, यह पकड़ में आएगा नहीं। अतुल जी ने उन्हें समझाया भी कि वह पैसे के प्रलोभन में भी नहीं आता। एक सत्र की अध्यक्षता उसे ऑफर की थी, लेकिन साफ मना कर दिया, अंत में यह अध्यक्षता हमें अनुराग जी को देनी पड़ी। चौथा संभागी कुछ समझदार किस्म का था, वह बोला- 'यार हमें क्या, नहीं आता है तो नहीं आए। हमारे क्या फर्क पड़ेगा भाड़ में जाए।' पहले वाले की शंका बरकरार थी, उसने कहा- 'और उसकी चर्चा मुफ्त में ही हो गई तो हम क्या करेंगे?' दूसरे ने कहा- 'यह हमारे लिए ढूब मरने वाली बात होगी। मेरा कहा मानो और पत्रवाचकों को पहले ही समझाओ ताक हमारे आयोजन का लाभ उसके पक्ष में न जाए।'







